भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 713
जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2026 को दिया जाना है ।
02 श्रावण, 1948 (शक)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा केन्द्र की स्थापना

713. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित कृत्रिम बुद्धिगत्ता डेटा केन्द्र (एआई डेटा सेंटर) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसके अंतर्गत प्रस्तावित कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम संसदीय एवं विधिक डेटाबेस का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए इसी प्रकार के डोमेन विशिष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता ज्ञान भंडार विकसित करने का विचार रखती है; और
(ग) शासन एवं सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों के विकास हेतु ऐसे ज्ञान भंडारों के उपयोग के लिए तैयार की गई रूपरेखा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** भारत की एआई नीति प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण हेतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना पर आधारित है। इंडियाएआई मिशन के तहत, सरकार एक संप्रभु एआई स्टैक विकसित कर रही है, जिसमें गणना क्षमता, मूलभूत मॉडल और स्वदेशी अनुप्रयोग शामिल हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एआई कंप्यूट क्षमता ढांचे के तहत 15 सूचीबद्ध सेवा प्रदाताओं और डेटा केंद्रों से ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय डेटा सेंटर में 248 जीपीयू की विशेषता वाली एक जीपीयू-आधारित कंप्यूट सुविधा स्थापित की जा रही है। इस अवसरंचना को विभिन्न सरकारी विभागों को महत्वपूर्ण एआई अनुमान सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

<u>सरकारी क्षेत्र में एआई पहलें</u>

कई एआई-संचालित सेवाएं वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में चालू हैं। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में प्रमुख पहलों में निम्नलिखित को शामिल किया गया हैं:

- संसदीय प्रक्रियाओं, नियमों और संवैधानिक निर्देशों में सहायता के लिए एनआईसी द्वारा लोकसभा सचिवालय के लिए एक बॉट का विकास
- इंडिया कोर्ट पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय कानूनों, नियमों और अधिसूचनाओं तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए एनआईसी द्वारा विधायी कार्य विभाग के लिए एक बॉट सृजन
- कृषि क्षेत्र में भारत विस्तार पहल, किसानों को स्थानीयकृत फसल संबंधी परामर्शी निदेश, बाजार मूल्य और मौसम संबंधी अपडेट प्रदान करने के लिए एक बहुभाषी मंच के रूप में कार्य करती है
- नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल प्रणाली, जो छाती के एक्स-रे अपलोड के माध्यम से तपेदिक (टीबी) का शीघ्र पता लगाने के लिए एआई-सहायता प्राप्त रेडियोलॉजिस्ट हस्तक्षेप को सक्षम बनाती है
- छात्रों की पहुंच बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के लिए एनआईसी द्वारा बहुभाषी चैटबॉट की सुविधा प्रदान की गई

<u>एआई मॉडल विकास रोडमैप:</u>

भारत सरकार बड़े भाषा मॉडल विकसित करने के लिए भारतीय स्टार्टअप और संस्थानों का समर्थन कर रही है। सहायता के लिए 20 स्वदेशी सॉवरेन मॉडल प्रस्तावों की पहचान की गई है, जिसमें 12 वृहत भाषा मॉडल (एलएलएम) और 8 लघु भाषा मॉडल (एसएलएम) शामिल हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियों में सर्वम एआई के 30बी और 105बी पैरामीटर मॉडल, ज्ञानी.एआई का स्पीच-टू-स्पीच मॉडल, भारतजेन के बहुभाषी फाउंडेशन मॉडल और अवतार एआई का वीडियो-जनरेशन मॉडल शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, एआईकोश राष्ट्रीय डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो 578+ संगठनों के 22 क्षेत्रों में 13,445 से अधिक डेटासेट तक पहुंच प्रदान करता है। यह एआई समाधानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 329 एआई मॉडल और 202 प्रलेखित उपयोग के मामलों की भी मेजबानी करता है।

*****